संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

19th February, 2024

DO No. 08/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

"True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it"

The above lines by Aristotle, the ancient Greek philosopher , emphasize the importance of intellectual flexibility, open-mindedness, and critical thinking and simultaneously urge us to engage with different perspectives and ideas.

I believe that the confluence of ideas provides the necessary oxygen to innovation as well as systemic improvements. In this spirit, the Conference of the (Pr.) Chief Commissioners of Customs was organized last week. The agenda of the two day Conference was comprehensive and wide. I am happy that the discussions were not top-driven and were founded on practical considerations. Partner Government Agencies (PGAs) play a crucial role in expedited customs clearance by collaborating with customs authorities to facilitate efficient and streamlined EXIM clearance processes. Their involvement in such conferences is a good beginning as it provides a platform to engage with some of the PGAs to further our shared goal – facilitation of trade.

As you might recall, at the start of this year, I had indicated my desire to bring about standardization in the implementation of Indian Customs' initiatives. For me, one of the major takeaways of the Conference was the push towards uniformity in various aspects of Customs processes.

I would also like to mention the meeting held last week between CBIC and Ms. Christine Stevenson, Comptroller, New Zealand Customs. The discussions involved cooperation on enforcement, capacity-building opportunities, measures to boost trade and avenues for future bilateral engagements.

It goes without saying that the machinery of GST is a stellar example of cooperative federalism between the Centre and the States. The strengthening and capacity building of the tax administrations of both the Centre and States will go a long way in providing improved taxpayer services. In this regard, NACIN signed an

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

MoU with the Excise and Taxation Department, Government of Haryana for capacity building and training the officers of Excise and Taxation Department of Haryana. Similarly, NACIN Palasamudram recently conducted a comprehensive three-day training of senior Andhra Pradesh State GST officers in the areas of audit, investigation, adjudication and arrear recovery. I am sure such collaborations will enhance synergy between the Centre and States.

I would like to laud the efforts of Nagpur Customs Commissionerate who foiled the attempt to illegally export 82.93 MT of onion which has been prohibited by the Government of India till March 2024. To evade being detected, the exporters had mis-declared goods as 'tomatoes'.

In another case worth mentioning, officers of Motihari Division of Patna Customs (P) Commissionerate, based on specific intelligence, seized Garlic of Chinese origin which is considered a pertinent health hazard. About 64,000 Kgs of Garlic, worth Rs. 1.3 crores, was attempted to be smuggled into the country at a remote border area of Bihar-Nepal Border near Sikta Land Customs Station. However, our officers with the assistance of SSB intercepted the goods. Kudos to the team!

Till next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

19th February, 2024

DO No. 08/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

"True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it"

प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू की उपरोक्त पंक्तियाँ बौद्धिक विचार, स्वतंत्र विचारधारा और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देती हैं और साथ ही हमें विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों के साथ जुड़ने का आग्रह करती हैं।

मेरा मानना है कि विचारों का संगम नवाचार के साथ-साथ प्रणालीगत सुधारों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसी भावना से, पिछले सप्ताह सीमा शुल्क के (प्र.) मुख्य आयुक्तों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। दो दिवसीय सम्मेलन का एजेंडा व्यापक एवं विस्तृत था। मुझे ख़ुशी है कि चर्चाएँ शीर्ष आधारित नहीं थीं और वास्तविक विचारों पर आधारित थीं। साझेदार सरकारी एजेंसियां (PGAs) कुशल और सुव्यवस्थित EXIM प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ सहयोग करके त्वरित सीमा शुल्क निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे सम्मेलनों में उनकी भागीदारी एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि यह हमारे साझा लक्ष्य - व्यापार की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ PGA के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

जैसा कि आपको याद होगा, इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने भारतीय सीमा शुल्क पहल के कार्यान्वयन में मानकीकरण लाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। मेरे लिए, सम्मेलन का एक प्रमुख निष्कर्ष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं में एकरूपता की ओर जोर देना था।

मैं पिछले सप्ताह सीबीआईसी और सुश्री क्रिस्टीन स्टीवेन्सन, नियंत्रक, न्यूजीलैंड सीमा शुल्क के बीच हुई बैठक का भी उल्लेख करना चाहूंगा। चर्चा में प्रवर्तन, क्षमता निर्माण के अवसरों, व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों और भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर सहयोग शामिल था।

कहने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी की मशीनरी केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण है। केंद्र और राज्यों दोनों के कर प्रशासनों की मजबूती और क्षमता निर्माण से बेहतर

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

करदाता सेवाएं प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में, NACIN ने हरियाणा के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए हरियाणा सरकार साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह, NACIN पलासमुद्रम ने हाल ही में ऑडिट, जांच, निर्णय और बकाया वसूली के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश राज्य जीएसटी के वरिष्ठ अधिकारियों का एक व्यापक तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। मुझे यकीन है कि इस तरह के सहयोग से केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा।

मैं नागपुर सीमा शुल्क आयुक्तालय के प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने 82.93 मीट्रिक टन प्याज के अवैध निर्यात के प्रयास को विफल कर दिया, जिसे भारत सरकार ने मार्च 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया है। बचने के लिए, निर्यातकों ने माल को 'टमाटर' घोषित किया था।

उल्लेखनीय एक अन्य मामले में, पटना सीमा शुल्क (P) आयुक्तालय के मोतिहारी डिवीजन के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर, चीनी मूल के लहसुन को जब्त कर लिया, जिसे एक प्रासंगिक स्वास्थ्य खतरा माना जाता है। करीब 64,000 किलोग्राम लहसुन, जिसकी कीमत रु. 1.3 करोड़ रुपये की थी, को सिकटा लैंड कस्टम स्टेशन के पास बिहार-नेपाल सीमा के सुदूर सीमावर्ती इलाके में देश में तस्करी करने का प्रयास किया गया था। हालाँकि, हमारे अधिकारियों ने एसएसबी की सहायता से सामान को रोक लिया। टीम को बधाई!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण ।